700वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 दिसम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 700वीं बैठक दिनांक 14/12/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9958/2023 Shri Sudhir Choudhary, Owner, R/o Ward No. 26, Prem Nagar, Tehsil & District-Balaghat (MP)- 481001, Prior Environment Clearance for Bhanpur Crusher Stone Quarry in an area of 4.173 ha. (30001 Cum per annum) (Khasra No. 41 P), Village-Bhanpur, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP) B2. QR.</u>

प्रकरण समिति की पूर्व 655वीं बैठक दिनांक 22/6/23 का प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें **परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश–देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश–देशांश से नहीं होता है अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को–आर्डिनेट पुनः प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का क्षेत्र दर्शित हो सके।**

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण समिति की 666वी बैठक दिनांक 04/08/23 डिलिस्ट कर सिया को भेजा गया था । प्रकरण सिया द्वारा रि–लिस्ट कर समिति को पुनः प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 14/12/23 को समिति के सक्षम रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक सुधीर चौधरी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीरण के दौरान खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज विभाग), जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 1086 दिनांक 27/09/2023 के माध्यम से खदान के डी.जी.पी.एस. को–आर्डिनेट प्रस्तुत किये गये। समिति द्वार संशोधित को–आर्डिनेट पर आधिारित गूगल ईमेज से प्रकरण का परीक्षण किया गया, खदान क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने सरफेस मेप में दर्शाया है। खदान क्षेत्र में कुछ पेड है जिन्हे

काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ घर एवं रोड स्थित है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है अतः 100 मी. तक का क्षेत्र गैर–खनन क्षेत्र के रूप मे छोडा गया है। पश्चिमी दिशा में लगभग 122 मी. की दूरी पर प्राकृतिक नाला स्थित है।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

1. आवंटित खनन् क्षेत्र में कई पेड़ लगे है अतः उनकी इंवेट्री तथा समिति द्वारा सुझाए अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
2. खदान क्षेत्र के आस पास स्थित पर्यावरण संवेदशीलता के फीचर्स एवं गैर–खनन क्षेत्र को दशार्ते हुए पुर्नरक्षित सरफेस मे।
3. पुर्नरक्षित प्रोडक्शन मेप।

2. <u>Case No 9940/2023 Shri Balveer Parmar, R/o Krishna Dham Colony, Depalpur, District-Indore (MP)- 453115, Prior Environment Clearance for Sagdod Stone Mining in an area of 4.00 ha. (10070 cum per annum) (Khasra No. 843/2/2, 843/1/3, 843/2/1), Village- Sagdod, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP).TOR.</u>

प्रकरण समिति की पूर्व की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई गूगल इमेज में खदान का रकबा 0.1 हे. दर्शाया गया है जबकि अन्य दस्तावेज अनुसार खदान क्षेत्र का रकबा 4.0 हे. उल्लेखित है । अतः समिति चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निदेर्शित किया कि उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए परिवेश पोर्टल पर गूगल इमेज में खदान का वास्तविक रकबा उल्लेख करते हुए परिवेश पोर्टल पर अपलोड करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023 को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर परमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विजय मिश्रा, जियोग्रीन इंवायरो हाऊस प्रा.लि.लखनऊ उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि **खनिज अधिकारी,** कार्यालय कलेक्टर, (खनिज विभाग), जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 146 दिनांक 20/01/2023 के माध्यम से अनुसार 500 मी. की परिधि में स्थित खदानों का कुल रकबा 6.150 हे. है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. आवंटित खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. खदान क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्य होना दृष्टिगोचर नहीं हो रहें है। अतः प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) प्रस्तुत करें साथ ही खनिज अधिकारी से उक्त माइनिंग क्षेत्र के खनन्कर्ता कौन है उसकी सूची भी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. सरफेस रन ऑफ स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. माइनिंग किये जाने से आसपास के खेतों में क्या दुष्प्रभाव होंगें, इस संबंध में अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें
5. खदान क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु जगह –जगह गढ्ढे खुदे हुये है, इन गढ्ढों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण कार्य हेतु किया गया था व इन पर कितना व्यय हुआ की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

3. <u>Case No 10305/2023 Shri Vishnu Singhal, Partner, R/o Near Shrinath Brick Factory, Ajapura, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Chaudpur Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2001 cum per year) (Khasra No. 132/2), Village-Chodpur, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) B2.</u>

प्रकरण समिति की पूर्व की 679वीं बैठक दिनांक 14/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

- **कृषि भूमि के संबंध में पटवारी से फसल का 03 वर्ष की जानकारी लेना है,**
- **तथा सी.ई.आर योजना के अंतर्गत भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ में जमा करने का परियोजना प्रस्तावक वचनपत्र प्रस्तुत करें।**

- **अधिकृत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से 03 फूट गहराई का मृदा परीक्षण प्रस्तुत करे। NPK एवं कार्बन की मात्रा का विश्लेषण प्रस्तुत करे।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु सिंहल ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दिए गए प्रस्तुतीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाईल –2001 मी3 प्रति वर्ष होगी।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपिटल राशि रू. 13.35 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 3.10 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
शासकीय एकीकृत शाला चौङपुर की मरम्मत एवं फर्निचर (10 नग बेंच व डेस्क)	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	800
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन,	300

		कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये ।
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. **<u>Case No 10183/2023 Shri Amit Bhawsar, Proprietor, M/s Sundaram Suppliers, R/o Khargone District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Mominpura Crusher Stone and M-Sand Quarry in an area of 2.853 ha. (Stone-Gitti-10080, M-Sand-7020 cum per year) (Khasra No. 05), Village- Mominpura, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP).B-2</u>**

प्रकरण समिति की पूर्व की 679वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से 18/10/17 को जारी हुई है एंव खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पालन होना चाहिऐ था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित भावसार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए।

समिति ने निर्णय लिया कि चुकी प्रकरण डिया से सिया को री–एपराईजल हेतु प्राप्त है अतः डिया द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन के साथ परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.

3. Depiction of sensitive features existing within 500 meter radius around the lease area on surface map with prescribed set – back (if any applicable).
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

5. <u>Case No 7417/2020 M/s Deep Industries, Shri Amit Mishra, 402, Badagaon Gate, Bahar, Dist. Jhansi, UP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (8,820 to 1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 306), Village - Babai, Tehsil - Niwari, Dist. Niwari (MP) (EIA Presentation)</u>

प्रकरण समिति की पूर्व की 684वीं बैठक दिनांक 30/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

<u>समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि :–</u>

- सिया के पत्र क्रमांक 1596 दिनांक 05/08/21 के द्वारा मा. एनजीटी के ओए नं. 44/21 में पारित आदेश दिनांक दिनांक 29/11/21 की प्रति प्रेषित कर प्रकरण का परीक्षण करने का उल्लेख है ।
- परियोजना **प्रस्तावक** द्वारा क्षमता विस्तार पत्थर–8,820 to 1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।
- पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति श्री कैलाश गुप्ता के नाम पर जारी हुई थी, जो तत्पश्चात वर्ष 2019 में पर्यावरणीय स्वीकृति श्री अमित मिश्रा के नाम से हस्तांतरित हुई।
- सिया के पत्र क्र. 2782 दिनांक 12.01.2022 में परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि फ्रेस केस के रूप में आवेदन करें।
- परियोजना **प्रस्तावक** द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8820 प्रविर्ष की दर से 05 साल में 44100 घन मी निकालना था जिस के विरूद्ध पी.पी ने 19597 घन मी. स्टोन 2019 तक निकाला है।
- सी.टी.ओ 25/05/2019 का अवलोकन किया गया। पुरानी सी.टीओ का कोई कंपलाईन्स जमा नहीं किया गया अतः पुराने पी.पी पर कार्यवाही प्रस्तावित है। पूर्व में कैलाश गुप्ता को सीटीओ को वर्ष 2019 को जारी हुआ था जिस का कम्पलाईन्स नहीं हुआ है। और न उस का पालन प्रस्तुत हुआ 2019 का सीटीओ जारी किया गया था उस का भी पालन प्रतिवेदन पूर्व पीपी द्वारा जमा नहीं किया गया अतः समिति को चिंता है की सीटीओ का पालन हों रहा है या नहीं उस का विचार किया जाना होगा।
- विड ब्रेकिंक वाल का अपूर्ण निर्माण होना पाया गया।
- पूर्व शर्तो के अनुसार 45 पौधं प्रति हे. लगााने थे परन्तु 80 से 90 पौधो का रोपण किया गया है अतः शर्त अनुसार पोधे लगाकर पुनः प्रस्तुत करें।
- परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के 52 मी. एवं 176 मी. पर जो शेड दिखाई दे रहे है वे मुर्गीपालन केन्द्र है एवं इनको गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा गया है।

- जो समाजिक कार्य किये जाने थे नहीं किये गये। चुकी पूर्व की सामजिक जिम्मेदारी नहीं उठाई गई तथा एक्सपेशंन में जनसुनवाई अनुसार 01 लाख रूपये के कार्यो पर सहमति दी गई है परन्तु पुरानी जिम्मेदारी को भी पी.पी को निभाये जाना है अतः 01 लाख रूपये पुरानी तथा नई सामाजिक जिममेदारी 03 लाख रूपये का प्रस्ताव दे इस प्रकार 04 लाख की सामाजिक जिममेदारी नये पीपी द्वारा स्वीकार की जाती है।
- एम. ओ. ई. एफ. का पालन प्रतिवेदन में की रिपोर्ट में बिन्द ुक्रमांक 10 पर मानक शतों में दर्शाया गया है जिसमें ट्रेंच व गारलैण्ड ड्रेन बनाने की शर्त पूर्व ई.सी में दी गई थी कंपलाईन्स रिपोर्ट में पूर्ण बताई गई थी परन्तु पीपी ने बताया उक्त कार्य को नहीं किया गया है जिसे वह पूर्ण करेगें इस आशय का पत्र भी प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया है।

<u>प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :</u>

- परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र की एम ओ ई एफ का पालन प्रतिवेदन में जो कंपलाईन्स कार्य अपूर्ण है वे कार्य 01 वर्ष में पूर्ण कर लिये जावेगें।
- जियो–हाईड्रोलॉजिकल स्टडी प्रस्तुत की जाये।
- पूर्व शर्तो के अनुसार 45 पौधे प्रति हे. लगााने थे परन्तु अभी तक मात्र 80 से 90 पौधों का रोपण किया गया है अतः शर्त अनुसार पौधे लगाकर जियोटेग फोटो के साथ प्रस्तुत करें।
- ट्रेंच व गारलैण्ड ड्रेन बनाने की शर्त का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- समाजिक, आर्थिक जिम्मेदारी के अंर्तगत समिति द्वारा सुझाई गई गतिविधियों का प्रस्ताव मय बजट के प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित मिश्रा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि उक्त प्रकरण में सिया से पूर्व में ई.सी, प्रकरण क्रमांक 1943 (सिया की इसी पत्र क्रमांक 2838 दिनांक 03/03/2015) को द्वारा जारी की गई थी। सिया द्वारा जारी से पूर्व ई. सी का परीक्षण किया गया।

- पूर्व ई.सी के बिन्दु क्रमांक में 6 मीटर तक गहराई का प्रस्ताव है।
- पूर्व ई. सी में प्रस्तावित वृक्षा रोपण व समाजिक कार्य का लेखन किया गया था, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है क्या सामाजिक कार्य किया जायेंगा व कितनी धनराशि व्यय होगी इस विषय में कोई अभिलेख वर्तमान पीपी प्रस्तुत कर सके न रिकार्ड में है। अतः इन बिन्दुओ पर कोई परीक्षण नहीं किया जा सका।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- **रिवाईस्ड सरफेस एवं प्रोडक्शन प्लान प्रस्तुत करें।**
- **खदान एरिया की फेन्सिंग की कुल लंबाई कितनी है और अभी तक कितनी फेन्सिंग कर ली गई है एवं फेन्सिंग कार्य कब तक पूर्ण करगें पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।**
- **पूर्व ई.सी शर्तो का पालन प्रतिवेदन सूची बनाकर प्रस्तुत करें।**
- **पुर्नरक्षित वृक्षारोपण स्कीम**
- **समिति द्वारा सुझायें गयें प्रस्तावित सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट एवं समय सीमा के साथ प्रस्तुत करें।**

6. Case No 9997/2023 Shri DHARMENDRA PATIDAR, Proprietor, Devari Khawasa Stone (Gitti) Quarry Project Gram-Devri khawasa Teahsil-Manasa Dist-Neemuch (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone – 24,538 cum per annum, Waste - 2000 cum per annum) (Khasra No. 1839/2 (Govt.), Village DEWRI KHAWASA Tehsil Manasa District Neemuch (M.P.)

प्रकरण समिति की पूर्व की 671वीं बैठक दिनांक 24/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया **कि डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तो** के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पालन होना चाहिऐ था । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण संबंधी शर्तो का पालन नही दर्शाया गया **अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि** खदान में की गई फेंसिग के ज्योटेग फोटोग्राफ (03–04) जिसमें संपूर्ण खदान की वाऊड्री दिखाई देती हो एवं पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के शर्तो के अनुसार लगभग 1000 पौधे लगाये जाने थे **दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ / ड्रोन व्हीडियो सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक धर्मेद्र पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तुतीकरण के प्रांरभ में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. जारी हुई थी जो कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला नीमच के पत्र आदेश क्रमांक 298 दिनांक 05/03/2020 के तहत यह खदान नवीन परियोजन प्रस्तावक को अंतरण

हुई है, अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक के लिये यह नवीन प्रकरण है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन अपूर्ण पाया गया–

- **कोई भी पर्यावरण संबंधी कार्य पूर्ण नहीं पाया गया**
- **सरफेस मेप में ओल्ड माईन पिट दर्शाया गया है।**
- **खदान क्षेत्र में कशर प्रस्तावित है जो कि सरफेस प्लान में दर्शाया गया है।**
- **खदान क्षेत्र का ड्रोन विडियों देखा गया जिसमें फेन्सिग, वृक्षारोपण एवं ओवर वर्डन डम्प पाये गये।**

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- **खनिज अधिकारी से वर्षवार प्रोडक्शन प्लान, वर्तमान में कितनी गहराई तक कार्य किया गया है एवं डिया में स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुरूप खनन किया गया या नहीं, का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्त किया जावें।**
- **डिया की ई.सी शर्तो का पालन प्रतिवेदन (भौतिक लक्ष्य, बजट) की सूची बनाकर प्रस्तुत करें।**
- **खदान एरिया की फेन्सिंग की कुल लंबाई कितनी है और अभी तक कितनी फेन्सिंग कर ली गई है एवं फेन्सिंग कार्य कब तक पूर्ण करगें पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।**
- **खदान क्षेत्र में ओवर वर्डन डम्प पाये गये इनका प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।**
- **पुर्नरक्षित वृक्षारोपण स्कीम एवं खदान क्षेत्र में लगे हुये वृक्षों में से कितने वृक्ष कटेंगे एवं काटे जाने वाले पेडो की उन्ही प्रजाति के पौधों के 10 गुना लगाने का प्रस्ताव।**
- **समिति द्वारा सुझायें गयें प्रस्तावित सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट एवं समय सीमा के साथ प्रस्तुत करें।**
- **ईएमपी योजना में प्रस्तावित वृक्षारोपण का बजट प्रस्तुत करें।**

7. **Case No 10335/2023 Shri Gayaprsad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kherwakhurd Sand Deposit in an area of 4.614 ha. (46140 cum per year) (Khasra No. 201/248), Village-Kherwakhurd, Tehsil-Bandhavgarh, District-Umariya (MP)**

प्रकरण समिति की पूर्व की 683वीं बैठक दिनांक 29/9/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि **नदी के दक्षिण के तरफ मेजर ब्रिज परिलक्षित हो रहा है**

और उत्तर की दिशा में उपर की ओर मध्यम आकार का रोड ब्रिज के पाया जाता है इस प्रकार बडे ब्रिज से 1 कि.मी. लेने पर तथा मध्यम आकार से ब्रिज से 500 मी. लेने पर पूरी नदी क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र में आती। है। प्रस्तुतीकरण के दौरान माईनिंग आफिसर उपस्थित नहीं हुये थे, श्री दिवाकर चतुवेर्दी माईनिंग इंस्पेक्टर उपस्थित हुए जिनके द्वारा माईनिंग अफसर एवं ब्रिज कार्पोरेशन/ सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जारी पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष रखना चाहते परियोजना प्रस्तावक श्री अंजना जी ने भी समिति के समक्ष अनुरोध किया की उक्त खनन क्षेत्र से विगत 02 वर्ष में अधिकतम 16304 क्यू मी रेत प्राप्त किया जाना तथा रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के आधापर 13900 डीएसआर में उपलब्ध होना पाया गया है। जोकि रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के अनुरूप नही है। समिति ने निर्णय लिया कि उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक सेंड गाईडलाईन 2020 के पेज न. 24 पैरा "आर" अनुसार दिये गये रिफ्रेन्श के संबंध में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये ब्रिज कार्पोरेशन से अभिमत प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Gayaprsad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज जिला उमरिया का पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 04/10/2023 (जिसमें उल्लेख है कि डाउन स्ट्रीम से 500मी. एवं अप स्टीम पर 250 मी. की दूरी छोडकर नो– माईनिंग जोन चिन्हाकिंत किया है) के द्वारा अपने पत्र के माध्यम से कार्यालय महाप्रबंधक प्राप्त म.प्र ग्रामिण सडक विकास प्राधिकरण उमरिया का पत्र क्रमांक 1148 दिनांक 12/10/2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की, म.प्र ग्रामिण सडक विकास प्राधिकरण उमरिया के पत्र में उल्लेख है कलेक्टर खनिज जिला उमरिया का पत्र में वर्णित दूरी छोडते हुए रेत खनिज का खनन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने प्रकरण के समीक्षा के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप में कुल खनन क्षेत्र 4.164 हे. में से गैर खनन क्षेत्र 3.94 हे. एवं खनन क्षेत्र 0.4044 हे. दर्शाया गया है। अतः उपलब्ध खनन क्षेत्र में रेत उत्खनन की अधिकतम मात्रा–12,132 घनमीटर/वर्ष प्रस्तावित की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,132 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.88 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.93 लाख प्रति वर्ष ।

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, कछरवार के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी |	20,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5540 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1550
2	ग्राम खेर्वाखुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3990

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

8. <u>Case No 10368/2023 Shri Gayaprsad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Narwar Sand Mine in an area of 2.78 ha. (50040 cum per year) (Khasra No. 352), Village-Narwar, Tehsil-Chandla, District-Umariya (MP)-Query Reply.</u>

प्रकरण समिति की पूर्व की 683वीं बैठक दिनांक 29/9/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि नदी के दक्षिण के तरफ मेजर ब्रिज परिलक्षित हो रहा है और उत्तर की दिशा में उपर की ओर मध्यम आकार का रोड ब्रिज के पाया जाता है इस प्रकार बडे ब्रिज से 1 कि.मी. लेने पर तथा मध्यम आकार से ब्रिज से 500 मी. लेने पर पूरी नदी क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र में आती। है।** प्रस्तुतीकरण के दौरान माईनिंग आफिसर उपस्थित नहीं हुये थे, श्री दिवाकर चतुवेर्दी माईनिंग इंस्पेक्टर उपस्थित हुए जिनके द्वारा माईनिंग अफसर एवं ब्रिज कार्पोरेशन/ सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जारी पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष रखना चाहते परियोजना प्रस्तावक श्री अंजना जी ने भी समिति के समक्ष अनुरोध किया की उक्त खनन क्षेत्र से विगत 02 वर्ष में अधिकतम 16304 क्यू मी रेत प्राप्त किया जाना तथा रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के आधापर 13900 डीएसआर में उपलब्ध होना पाया गया है। जोकि रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के अनुरूप नही है। समिति ने निर्णय लिया कि उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक सेंड गाईडलाईन 2020 के पेज न. 24 पैरा "आर" अनुसार दिये गये रिफ्रेन्श के संबंध में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये ब्रिज कार्पोरेशन से अभिमत प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Gayaprsad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज जिला उमरिया का पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 04/10/2023 (जिसमें उल्लेख है कि डाउन स्ट्रीम से 500मी. एवं अप स्टीम पर 250 मी. की दूरी छोडकर नो– माईनिंग जोन चिन्हाकिंत किया है) के द्वारा अपने पत्र के माध्यम से कार्यालय महाप्रबंधक प्राप्त म.प्र ग्रामिण सडक विकास प्राधिकरण उमरिया का पत्र क्रमांक 1149 दिनांक 12/10/2023 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की, म.प्र ग्रामिण सडक विकास प्राधिकरण उमरिया के पत्र में उल्लेख है कलेक्टर खनिज जिला उमरिया का पत्र में वर्णित दूरी छोडते हुए रेत खनिज का खनन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने प्रकरण के समीक्षा के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप में कुल खनन क्षेत्र 2.78 हे. में से गैर खनन क्षेत्र 2.41 हे. एवं खनन क्षेत्र 0.222 हे. दर्शाया गया है। अतः उपलब्ध खनन क्षेत्र में रेत उत्खनन की अधिकतम मात्रा–6660घनमीटर/वर्ष प्रस्तावित की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–6660 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.49 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.89 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय बहेर्वाह के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	**10,000**

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3336 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम नरवार के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3336

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

9. Case No 10508/2023 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance

for Bakamukasa Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (14100 cum per year) (Khasra No. 350), Village-Bankamukasa, Tehsil-Amarwara, District-Chhindwara (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान प्रस्तावित खदान की केएमएल इमेज से **मिलान** नहीं हो रही है। **अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि खदान के अक्षांश–देशांश की संख्या बढ़ाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करे** ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं सहायक खनिज अधिकारी श्री महेश नागपुरे उपस्थित हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज का पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 13/10/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के 08 कार्डिनेट्स प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा लीज क्षेत्र डूबा हूआ होने के संबंध में बताया कि मार्च एंव अप्रैल माह में नदी में पानी नही रहता है जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है। समिति ने संबंधित परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि अतिरिक्त कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सिया/सेक को प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–14,100 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.58 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.25 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Bakamukasa	15,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

10. Case No 10492/2023 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Lonikala Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4800 cum per year) (Khasra No. 240), Village- Lonikala, Tehsil- Chand, District- Chhindwara (M.P.)

प्रकरण समिति की पूर्व की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान प्रस्तावित खदान की केएमएल इमेज से **मिलान** नहीं हो रही है। **अतः समिति**

ने परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि खदान के अक्षांश–देशांश की संख्या बढ़ाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा एवं सहायक खनिज अधिकारी श्री महेश नागपुरे उपस्थित हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज का पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 13/10/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के अतिरिक्त 08 कार्डिनेट्स प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी/परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शाया कि उत्तर दिशा में एक स्टाप डेम लगभग 01 कि.मी. पर स्थित है। समिति ने संबंधित **परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि** अतिरिक्त कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सिया/सेक को प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–4800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.32 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.14 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6,500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Lonikala	6,500

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1300 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	900

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

11. <u>Case No 10511/2023 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Ambadi Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (23040 cum per year) (Khasra No. 280), Village-Ambadi, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)</u>

प्रकरण समिति की पूर्व की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। **प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान प्रस्तावित खदान की केएमएल इमेज से मिलान नहीं हो रही है एवं केएमएल इमेज का एरिया 3.55 हे. है जबकि खदान का वास्तविक एरिया 4.0 हे. प्रस्तावित है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के multipul locations पर अक्षांश–देशांश लेकर पुनरिक्षित केएमएल इमेज तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करे।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के

700वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 दिसम्बर 2023

अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा एवं सहायक खनिज अधिकारी श्री महेश नागपुरे उपस्थित हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज का पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 13/10/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के अतिरिक्त 08 कार्डिनेट्स प्रस्तुत किये गये। समिति ने संबंधित **परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि** अतिरिक्त कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सिया/सेक को प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–23040 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.98 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.42 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Ambadi	20,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1900 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	800
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1100

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

12. Case No 10501/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक संभागीय कार्यालय टीकमगढ़), MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Tanga Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (8400 cum per year) (Khasra No. 800), Village-Tanga, Tehsil-Jatara, District-Tikamgarh (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। **प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान प्रस्तावित खदान की केएमएल इमेज से मिलान नहीं हो रही है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के multipul locations पर अक्षांश–देशांश लेकर पुनरिक्षित केएमएल इमेज तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करे।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज का पत्र क्रमांक 920 दिनांक 13/10/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के अतिरिक्त 14 कार्डिनेट्स प्रस्तुत किये गये। समिति ने संबंधित **परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि** अतिरिक्त 14 कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सिया/सेक को प्रस्तुत करें।

700वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 दिसम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–8400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.95 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.67 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय मितौरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	200
2	**ग्राम तांगा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न

होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

13. Case No 10493/2023 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pareghat-B Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (12180 cum per year) (Khasra No. 180), Village-Pareghat-2, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व की 689वीं बैठक दिनांक 13/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। **समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि खदान के बीच में से एक जल रोकन की संरचना/कच्चा रास्ता दिख रहा है। उपस्थित सहायक खनिज अधिकारी श्री महेश नागपुरे द्वारा अवगत कराया गया कि यह अस्थाई प्रकृति की संरचना है तथा वर्तमान में कोई संरचना यहां पर स्थित नहीं है। समिति ने सहायक खनिज अधिकारी को निर्देश दिया कि इस विषय के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें, तदुपंरात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द मिश्रा एवं सहायक खनिज अधिकारी श्री महेश नागपुरे उपस्थित हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज का पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 13/10/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के अतिरिक्त 08 कार्डिनेट्स प्रस्तुत किये गये तथा खदान के बीच में से एक जल रोकन की संरचना/कच्चा रास्ता के संबंध में सहायक खनिज अधिकारी श्री महेश नागपुरे द्वारा पत्र क्रमांक 1215 दिनांक 17/10/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये एवं अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोई संरचना /कच्चा रास्ता लीज क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह संरचना वर्ष 2020 के गूगल ईमेज में परिलक्षित हो रही थी। समिति ने संबंधित परियोजना प्रस्तावक/खनि अधिकारी को निर्देश दिये कि अतिरिक्त 14 कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सिया/सेक को प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–12,180 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

700वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 दिसम्बर 2023

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.84 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.33 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Pareghat-B	10,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	760
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	940

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

14. Case No 8732/2021 Shri Kanhaiyalal Parmar S/o Shri Bherulal Parmar, Ward No. 4, Kanad Agar, Dist. Agar Malwa, MP - 456441 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.767 ha. (10104 cum per annum) (Khasra No. 142/1), Village - Arniya, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP).

प्रकरण समिति की पूर्व की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

परियोजना प्रस्तावक श्री कन्हैया लाल परमार द्वारा बैठक में प्रस्तुत अपलोडेड गुगल ईमेज (के.एम.एल) के आधार पर समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र के अंदर कुछ बिजली के खंबे दिखाई दे रहे है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित बिजली के खंबे/इंलेक्ट्रक लाईन डालने का प्रस्ताव निरस्त हो गया है। परन्तु श्री कन्हैया लाल परमार इस संबंध में काई भी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत नही कर सके । अतः समिति परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि पहले सक्षम प्राधिकरण से बिजली के खंबे/इंलेक्ट्रक लाईन डालने का प्रस्ताव निरस्त होने की जानकारी प्रस्तुत करे तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Kanhaiyalal Parmar एवं उनकी ओर से **श्री उमेश मिश्रा** पर्यावरण सलाहकार **मेसर्स केएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए।**

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कनिष्ठ यंत्री ,म.प्र.प.क्षें.वि. वि.कंपनी कानड का पत्र क्रमांक 3066 दिनांक 25/10/2023 के माध्यम प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे क्रमांक 142/1 रकबा 1.767 पर वितरण केन्द्र कनाड के अंतर्गत आने वाली लाईन 33 केव्ही लाईन अथवा पोल स्थापित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दिए गए प्रस्तुतीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 10104 मी3 प्रति वर्ष होगी।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपिटल राशि रू. 04.78 लाख एवं रिक्रंरिंग राशि रू. 01.63 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अनुरोध के अनुसार अरनिया की आंगनबाडी के लिए स्कूल डेस्क व कुर्सी का सेट 5,	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1963 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 65)सेमी x 65सेमी (|	खमार, सिस्सू, अमलतास, खिरनी, नीम, कालासिरिस, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी।	863
2	परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण 01 पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई) (मीटर|	अमलतास, खिरनी, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय | ट्री गार्ड के साथ-	100
3	ग्राम अरनिया के स्कूल, ग्राम पंचायत भवन आगनवाडी के प्रांगण एवं बंजर शासकीय भूमि में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	500
4	अरनिया के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		कुल	

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No 10574/2023 M/s Samdariya Builders (Bhopal) Private Limited, Owner, House No. 16, Sunarhaai Chowk, Sarafa Bazar, Samdariya Abhushan Bhandar, Sarafa, Sarafa ward, Jabalpur, Prior Environment Clearance for Samdariya Gold Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).B-2.

Earlier the case was presented in the SEAC 691st meeting dated 18.10.2023 wherein after presentation the committee has sought following information along with the supporting documents from the PP & their consultant –

1. Clarify the clause of the agreement made with Railways regarding the payment of lease rent to Railways i.e. whether the lease rent shall be paid by the purchaser of the property or by the developers.
2. Water requirement during construction phase – please clarify the quantum and the vendor or supplier of the water.
3. Water balance during operation phase clarifying the quantum of treated waste-water to be re-cyled.
4. Detailed proposal for dual plumbing so as to use the treated sewage in flushing.
5. Proposal for Solar power generation / use shall be enhanced to 30% of the total power requirement in the industry.
6. CER activities to be revised & re-submitted as per the provisions of MoEF & CC.
7. Regarding approval of lay-out by the T&CPO it was submitted by the PP that a letter has been written by the T&CPO seeking comments from railways on applicable provisions of Railway Acton this project. The response received from Railway to be furnished.
8. Revised plantation scheme to be submitted with provision of Green cover area 25%.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08/11/23 को अपलोड कर दी गई है, प्रकरण आज दिनांक 14/12/23 को समिति के समक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक सी.जे.पी. व्यवहार और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के लिये जल की आपूर्ति वेंडर (सुविधा वाटर सप्लायर्स) के द्वारा की जावेगी।

बैठक मे प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

- स्पष्ट करें कि जल की आपूर्ति हेतु नियुक्त वेंडर (सुविधा वाटर सप्लायर्स) नगर निगम से अधिकृत है या नहीं।
- प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले एसटीपी का स्पेशिफिकेशन(साईज एवं क्षमता) प्रस्तुत करें।
- प्रस्तावित परियोजना के प्रत्येक ब्लॉक में स्टाफ एवं आगन्तुकों के लिये जनसुविधाओं का प्रस्ताव बजट के साथ ईएमपी में शामिल कर प्रस्तुत करें।
- प्रस्तावित परियोजना के लिये हरित पट्टी के विकास का प्रस्ताव ले आउट में दर्शातें हुये बजट के साथ ईएमपी में शामिल कर प्रस्तुत करें।
- समिति द्वारा सुझायें गई सीईआर योजना जिसमें माधवराव स्प्रे संग्राहलय में अद्योसंरचना विकास एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान, सलैया स्कूल में अद्योसंरचना विकास एवं कौशल दक्षता विकास, वन विहार हेविटेट डेव्हलेपमेन्ट, एकलव्य आवासीय स्कूल (शाहपुरा थाने के पास, भोपाल) में अद्योसंरचना विकास एवं कौशल दक्षता विकास आदि प्रस्ताव में शामिल कर प्रस्तुत करे।

16. Case No 10648/2023 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Jatachaper Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jatachhapar, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व की 694वीं बैठक दिनांक 31/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र से लगभग 2.8 किमी पर एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि प्रस्तुत कॉर्डिनेटस से के.एम.एल. फाईल का मिलान नहीं हो रहा है अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कॉर्डिनेटस को सम्मिलित कर प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा एवं प्रभारी सहायक खनिज अधिकारी महेश नागपुरे उपस्थित हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर खनिज का पत्र क्रमांक 1344 दिनांक 01/11/2023 के माध्यम से लीज क्षेत्र के अतिरिक्त 11 कार्डिनेट्स प्रस्तुत

किये गये। समिति ने संबंधित प्रभारी सहायक खनिज अधिकारी को निर्देश दिये कि अतिरिक्त कार्डिनेट्स को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन करते हुये संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सिया/सेक को प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–3000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.23 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Jatachhapar	6,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	1000
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।			

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

17. Case No 10627/2023 Shri R.N. Shukla, Head Environment and Forest, M/s. Mahan Energen Limited Private Ltd., Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishnodevi Circle, S.G Highway, Ahmedabad (GJ)-382421, Prior Environment Clearance for Residential Township for Bandhaura Thermal Power Plant in an area of 9.10 Ha. at (Khasra No. 134, 135, 132, 131, 130, 144, 143, 145, 98, 146, 141/3, 141/1, 141/2, 139/1, 139/2, 140, 142) Village-Karsua, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [444647]. Total Built up Area - 43155.5 SqMt. Total Plot Area- 90,973.33 SqMt. (22.48 Acres). Cat. 8(a) Building Construction Projects.

This is case of Prior Environment Clearance for Residential Township for Bandhaura Thermal Power Plant in an area of 9.10 Ha. at (Khasra No. 134, 135, 132, 131, 130, 144, 143, 145, 98, 146, 141/3, 141/1, 141/2, 139/1, 139/2, 140, 142) Village-Karsua, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) in the 693th SEAC dated 20.10.2023.

The case was presented by PP Shri R.N. Shukla, Head Environment and Forest, M/s. Mahan Energen Limited and their Env Consultant M/s. Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd, Jaipur wherein following details were submitted:

Project Introduction:

- Mahan Energen Limited (MEL) a fully Owned subsidiary of Adani Power Limited (APL) is operating 1200 (2x600) MW & proposed Expansion of 1600 (2x800) MW coal based Bandhaura Thermal Power Plant situated at Singrauli District in Madhya Pradesh.
- MoEF&CC has grated Environmental Clearance for operating 1200 (2x600) MW & proposed expansion 1600 (2x800) MW of Bandhaura Thermal Power Plant in favour of Mahan Energen Limited vide letter J-13011/56/2006-IA.II (T) dated 20.04.2007, 27.07.2023.
- MEL has proposed Residential Township to cater the residential housing for employees, at Khasra No. 134, 135, 145, 146, 141/3, 141/1, 141/2, 139/1, 139/2, 140, 142, etc., Village Karsualal, Tehsil Mada, District Singrauli, Madhya Pradesh.

- The total plot area of the project is 90,973.33 sq. m. (22.48 Acres). The built-up area envisaged for the project is about 43,155.50 sq.m.
- The total Project Cost is Rs. 124 Cores.

The salient features of the project:

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/444647/2023.
2.	**Project Name**	Shri R.N. Shukla, Head Environment and Forest, M/s Mahan Energen Limited Private Ltd., Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishnodevi Circle, S.G Highway, Ahmedabad (GJ)-382421, Prior Environment Clearance for Residential Township for Bandhaura Thermal Power Plant in an area of 9.10 Ha. at (Khasra No. 134, 135, 132, 131, 130, 144, 143, 145, 98, 146, 141/3, 141/1, 141/2, 139/1, 139/2, 140, 142) Village-Karsua, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [444647]. Total Built up Area - 43155.5 Sqmt. **Cat. 8(a)Building Construction Projects.**
3.	Description of Project	The project involves the development of Residential Township for Mahan Energen Limited, at Village Karsualal, Tehsil Mada, District Singraulli, Madhya Pradesh to cater the residential demands for the employees of the TPP with 239 no. dwelling units including 2 BHK, 3BHK, Villas, Guest House, Club House, along with other facilities including Temple Shopping Complex, primary School, Dispensary etc.
4.	**Area details as per Form -1**	Total Plot Area : 90,973.33 sq. m. (22.48 Acres) m2 Total Built up Area – 43,155.50 sq. m.
5.	**Project Proposal**	New.
6.	**Project Cost**	124 Cr.
7.	**Lat./Log. As per Form -1**	Latitude : 24°0'14.58"N Longitude : 82°25'38.95"E Latitude : 24° 0'9.40"N Longitude : 82°25'38.29"E Latitude : 24° 0'4.63"N Longitude : 82°25'33.03"E Point -4 Point -5 Point -6 Latitude : 24° 0'9.64"N Latitude : 24° 0'12.65"N Latitude : 24° 0'18.83"N
8.	**Parking Area.**	Required Parking : 286 ECS Proposed Parking : 341 ECS
9.	**Water NOC**	PP Apply Letter No. 297 dated 01/09/2022.
10.	**Water Requrement**	Construction Phase : 30 KLD Operation Phase : 237.5 KLD • Fresh Water : 120.5 KLD

		• Recycled Water : 117 KLD • Source : WTP of MEL
11.	**DG set details**	100 KVA : 1 No. 50KVA : 1 No.
12.	**Env. Con**	Shri Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd. Jaipur, (Rajasthan).

Items	**Details**			
Project Name	Residential Township for Bandhaura Thermal Power Plant at Village Karsualal, Tehsil Mada, District Singrauli, Madhya Pradesh, India			
Total Plot Area	90,973.33 sq. m. (22.48 Acres)			
FSI/FAR	Particulars	FSI/FAR	Area	
	Standard/Permissible*	1.25	113,716.66 sq. m.	
	Achieved • Residential • Commercial	0.391 0.002	35.753 sq. m. 35,551 sq. m. 202 sq. m.	
Non – FAR Area	7402.5 sq. m.			
Gross Built up area	43,155.50 sq. m.			
Ground Coverage	Permissible* : 30% (27,291.99 sq. m.) Achieved : 12.14% (11,042.24 sq. m.)			
Green Area	29,049.35 sq. m. (31.93%) Proposed No of Trees: 2000 nos. approx			
Project facilities				
	2 BHK	3 BHK	Villas	Guest House
	108 nos.	72 nos.	2 units	52 units
	Other facilities: Club House, Temple, Shopping Complex, School, Dispensary			
Parking facilities	Required Parking* : 286 ECS Proposed Parking : 341 ECS			
Power requirement	Construction Phase			Operational phase
	Power Requirement : 85 KVA Source : TPP of MEL			Power Requirement : 2500 KVA Source : TPP of MEL
Power backup (During blackout/ emergency purpose only)	D.G Set Capacity	Number	Fuel	Fuel requirement
	50 kVA	1 No.	LDO/HSD	10 lt/hr
	100 kVA	1 No.		20 lt/hr
Proposed Renewable Energy	Solar PV: Efforts will be done for achieving 750 KW (30% of the Power Requirement)			

700वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 दिसम्बर 2023

<table>
<tr><td>Water requirement & source</td><td colspan="2">Total Water requirement : 30 KLD
Source : WTP of Mahan Energen Limited (MEL)</td><td>Total Water Requirement : 237.5 KLD
✓ Fresh Water : 120.5 KLD
✓ Recycled Water : 117 KLD
✓ Source: WTP of Mahan Energen Limited (MEL)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sewage treatment & disposal</td><td>Construction Phase</td><td colspan="2">Operational phase</td></tr>
<tr><td>Sewage Generation : 10 KLD
✓ Treatment & Disposal: Modular STP</td><td colspan="2">Sewage generated : 130 KLD
Sewage Treatment facility : 160 KLD
STP Technology : MBBR
Recycled Treated water : 117 KLD
✓ Flushing : 51 KLD
✓ Greenbelt & Landscaping : 66 KLD
Dried sludge from STP to be mixed with wet waste and processed in OWC, this will be used as manure for gardening.</td></tr>
<tr><td>RWH Structures</td><td colspan="3">Rainwater harvesting Pond : 1200 sq. m. (1 No.)
Annual Recharge : 45779.03 cu. m.</td></tr>
<tr><td>Solid Waste Generation and Management</td><td colspan="3">445 kg/Day
Biodegradable waste (60 %) : 267 kg/Day
Non-Biodegradable (40 %) : 178 kg/Day
➢ Organic waste convertor of Capacity 300 kg/day will be proposed. Wet Garbage will be treated in Mechanical Composting Unit - Organic Waste Convertor (OWC) and the compost generated would be used as manure for gardening purpose.
➢ The Inorganic waste (Non-Biodegradable waste) shall be collected & disposed off at designated/authorized common place by the Nagar Palik Nigam, Waidhan, Singrauli. Application for issue NOC for disposal of generated MSW has been submitted to Nagar Palika Nigam, Waidhan, Singrauli.</td></tr>
<tr><td>Project cost</td><td colspan="3">Rs. 124 Crores</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EMP Budget</td><td>Construction Phase</td><td colspan="2">Operation Phase</td></tr>
<tr><td>Capital Cost : Rs. 36 Lacs
Recurring cost : Rs. 15 Lacs</td><td colspan="2">Capital Cost : Rs. 865 Lacs
Recurring cost : Rs. 35 Lacs</td></tr>
<tr><td>Budget for CER activities</td><td colspan="3">Rs. 125 lacs</td></tr>
</table>

सेक की 693वीं मीटिंग दिनांक 20/10/2023 में प्रस्तुतीकरण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी :–

1. परियोजना प्रस्तावक यह स्पष्ट जानकारी प्रदान करें कि प्रस्तावित रहवासी कॉलोनी औद्योगिक परिसर का हिस्सा है या नहीं ? यह भी सुनिश्चित करें कि यदि परियोजना हेतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टी.एन.सी.पी.ओ.) का अनुमोदन आवश्यक हो तो तदानुसार कार्यवाही कर जानकारी प्रस्तुत करें।
2. सी.ई.आर योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक स्कूल के प्राचार्य से प्रस्तावित गतिविधियों हेतु पत्र प्राप्त करे एवं पी.एच.सी. में पदस्थ अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्तावित कार्यो के संबंध में मांग प्राप्त कर तदानुसार कार्यवाही कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
3. वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत कम से कम 2500 पौधों के रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

The project proponent submitted clarification on 16.11.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 693rd meeting held on 20.10.2023.

With regard to above query whether the proposed residential colony is a part of the industrial complex or not? Also ensure that if the approval of Town and Country Investment Department (T.A.C.P.O) is necessary for the project, then take action accordingly and submit the information. PP submitted that-

- The proposed residential township is a captive township forthe employee of Bandhaura Thermal Power Plant only.
- The proposed Residential Township is within land area of TPP and in possession of Mahan Energen Limited which isoutside of Municipal limits of Singrauli, therefore NOC from Gram Panchayat has already been obtained vide letter dated 03.10.2023.
- MoEF&CC has granted Environmtal Clearance for operating 1200 (2 x600) MW & proposed expansion 1600 (2 x800) MW of Bandhaura Thermal Power Plant in favor of MahanEnergen Limited on dated 20.04.2007, 27.07.2023.
- It is also submitted that the project planning and design has been done in line with the requirements of Madhya Pradesh Bhumi Vikas (MPBV) Rules, 2012.
- The building footprint and the other parameters related to FAR, ground coverage are well below the permissible normsas prescribed under MPBV Rules, 2012.

Regarding CER:

- The total budget earmarked for CER activities is Rs.125lakhs.
- The same will be spent on the detailed need basis.

- MEL is ensuring the committee CER budget will beutilized in consultation of nearby Schools,Hospitals/Dispensaries and Veterinarians also in needy &advised by local authorities,
- We would like to assure the Hon'ble SEAC that the CERbudget will be spent within the stipulated time.
- Details ofthe same will be submitted regularly to the SEIAA, MPPCB, MoEF&CC along with the Six-Monthly ECCompliance reports as conditions laid in theissued/granted in the Environmental Clearance.

Regarding Plantation :

- MEL is ensuring more than 2500 trees will be planted undertree plantation scheme in 31.92 % area of proposedResidential Township

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for proposed residential township for bandhaura thermal power plantby Mahan Energen Limited (Total Plot Area = 90,973.33 sq. m. (22.48 Acres), Total Gross Built up Area = 43,155.50 sq. m.) at Village-Karsualal, Tehsil-Mada, District-Singrauli, Madhya Pradesh. Category B, Item 8 (a)** subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.

v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, and Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
iv. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
v. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
vi. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
vii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All

demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement during operation phase is 237.50 KLD out of which 120.50 KLD is fresh water requirement and 117 KLD will be the total recycled water generated, out of which 51 KLD recycled water will be used for flushing and 66 KLD water will be used for horticulture.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. Rainwater storage pond having an area of 1200 sq. m and effective volume of 45779.03 cu. m. will be constructed and the stored rainwater will be reused for horticulture purposes.

xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity **- 160** KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 160 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes.

No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. The PP shall ensure power generation from non- conventional sources i.e. solar power etc. to achieve 30% of the total power consumption.

ii. Looking to the use of e-vehicles atleast 03 battery charging points per towers in the projects shall be provided.

iii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

iv. Outdoor and common area lighting shall be LED.

v. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building

envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

vi. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

vii. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.

viii. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. Total waste 445 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 267 Kg/day and non- organic waste 178 Kg/dayand these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.

ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.

iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity.

These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. **Green Cover**

i. Total 3000 trees shall be planted in the area of 29049.35 Sq. m. (31.93% of total plot area) which is developed as greenbelt development as follows:

Sr. No.	**Scientific Name**	**Common Name**
	Trees	
1	Peltophorum pterocarpum	Yellow Gulmohar
2	Azadirachta indica	Neem
3	Madhuca longifolia	Mahua
4	Putranjiva roxburghii	Putranjiva
5	Ficus benjamina	Ficus
6	Millettia pinnata	Karanj
7	Albizia saman	Rain Tree
8	Delonix regia	Gulmohar
9	Senna siamea	Kasod
10	Syzygium cumini	Jamun
11.	Manqifera indica	Mango
12.	Psidium quajava	Guava
13.	Manilkara zapota	Chiku
14.	Phyllanthus emblica	Amla

15.	Artocarpus heterophyllus	Jack Fruit
16.	Gmelina arborea	Gumhar
17.	Saraca asoca	Ashoka
18.	Cassia fistula	Amaltaas
19.	Mimusops elengi	Molshree
20.	Terminalia arjuna	Adun
21.	Dalberqia sissoo	Sisham
22.	Bombax ceiba	Semal
23.	Schleichera oleosa	Kusum
24.	Moringa oleifera	Drumstick
25.	Brahea	Palm
26.	Lagerstroemia speciosa	Zarul
27.	Aeqle marmelos	Bel
28.	Ficus virens	White fig

ii. Not tree will be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).

iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points
   d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Total proposed Parking's arrangement for 341 ECS (Open area parking 245 ECS &Stilt Floor parking 96 ECS).

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. Basic facilities like wash rooms and toilets for the use by employees, guard, gardeners, outside drivers and house hold workers shall be provided in appropriate numbers to avoid open defecation in the nearby areas.

ii. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
iii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
iv. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
v. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
vi. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vii. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP&Corporation Environment Responsibility

i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 8.65 Crore as capital and Rs. 0.35 Crore as recurring cost for this project.
ii. For this project PP has proposed Rs. 61.70 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for various activities as follows:
iii.

A. Education **Govt. Sec. Sr. School ,Bandhaura, Singrauli, Madhya Pradesh**				**Rs. Lac**
S. no	**Particulars**	**Nos.**	**Cost/Item Rs.**	**Amount**
1.	**Two class rooms Construction 40*80=320 Sq. ft.**	**3200 Sq. ft.*1**	**1200 Sq. ft.*1**	**38.40**
2.	**Table and chair will be provided for th student**	**100**	**700**	**0.70**
3.	**Toilets will be constructed for boys and girls**	**3**	**40000/-**	**1.20**
4.	**Sanitary pad machine**	**1**	**30,000**	**0.30**
5.	**Library for students**	**1**	**-**	**2.80**

6.	**Assembly area will be constructed 40*80=3200 Sq. ft.**	**3200 Sq. ft.*1**	**-**	**10.00**
7.	**Solar system roof top**	**10 KW**	**-**	**5.0**
8.	**Computers will be given in the school**	**10**	**25,000/-**	**2.50**
9	**Plantation with in school premises**	**200**	**200*400**	**0.80**
Total :				**61.70**

iv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

vi. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

18. Case No 10562/2023 Shri Pratav Singh Tomar, Owner, M/s Tomar Builders and Contractors Private Limited, R/o A-1/8, Vinay Nagar, Sector-4, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Keruaa Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (150000 cum per year) (Khasra No. 290), Village-Kairua, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP)

प्रकरण आज सेक की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

19. Case No 9269/2022 Shri Surendra Singh Saluja, Partner, M/s Madhya Pradesh Minerals Supply Company, 26/52, Alfartgand, Madhai ka Bagicha, B. D. Agrawal ward, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Bauxite, Laterite, Ochre, & White Earth Mine in an area of 15.78 ha. (Bauxite - 35273 Tonne per annum, Laterite - 4294 Tonne per annum, Ochre - 5040 Tonne per annum, Mineral Reject - 9370 Tonne per annum, Overburden - 4410 cum per annum) (Khasra No. 43(P)), Village - Kumhra Judwani, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP). EIA

700वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 दिसम्बर 2023

प्रकरण समिति की पूर्व की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थेः–

खदान के बीच से भी कच्चा रोड निकल रहा हैं, प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर तथा पूर्वी भाग से लगकर रोड़ निकल रही है,अत इसका संरक्षण हेतु मार्ग के दोनों ओर 45मी–45मी की दूरी छोड़कर कार्य किया जाएगा एवं मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा खदान में छेदन एवं विस्फोटन का कार्य भी नहीं किया जाएगा ।

समिति परीक्षण उपरांत पाया कि खदान क्षेत्र के आस–पास कुल 06 खदाने विगत् वर्ष में स्वीकृत हुई थी जिनमें पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई थी अतः पूर्व में स्वीकृत एवं संचालित खदानो के पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो विशेष रूप से वृक्षारोपण सीईआर की शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 14/12/2023को सम्पन्न बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री एन.पी. मिश्रा अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए ।

During presentation PP has submitted that there are four mines within 500m radius of subject mine which have been issued EC.

1. Saliaya Bauxite mine – 16.18ha- case no. 8930/2022 of M/s M P Minerals Supply,
2. Kumhra Judwani Bauxite mine – 15.78ha – Case No. 9168/2022 Of M/s Rakesh Agency
3. Kumhra Judwani Bauxite mine – 10.73ha – Case No. 9209/2022 Of M/s Jailal Bharatlal
4. Chitti Jangir Bauxite mine – 12.95ha – Case No. 9216/2022 of M/s Rakesh Agency

The consent under air and water act has also been obtained for these mines. However out of 04 mines which have been issued EC, out of them three of the mine have been lapsed and closed by the department of Mining. These three mines were operated for 02 months only. The detail on the desired information is as follows

Name of mine	Distance from subject mine	Status of consent to operate	Status of mine Operational /closed	Plantation done	Expenditure made under CER activities in RS

Saliya mines 16.18 Hact	290 m	From 07/10/2022 To 30/09/2027	Operational Since one year	743	32913+80000 + 50,000 = Rs 1,62,913
Chitti mine (Rakesh Agency-12.95 hact)	60 m	From 10/03/2023 To 29/02/2028	Closed **(Operated only for 02 months)**	464	Rs 41098
Kumhara Judwani 15.78ha (Rakesh Agency)	200 m	From 10/03/2023 To 29/02/2028	Closed **(operated only for 02 months**)	547	Rs 33866
Kumhara Judwani 10.73ha (jailal Bharatlal)	Adjacent	From 10/03/2023 To 29/02/2028	Closed **(operated only for 02 months)**	540	RS 30026

The PP further submitted that the issues raised in the Public hearing are addressed in the EMP and CER. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दिए गए प्रस्तुतीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Bauxite - 35273 Tonne per annum, Laterite - 4294 Tonne per annum, Ochre - 5040 Tonne per annum, Mineral Reject - 9370 Tonne per annum, Overburden - 4410 cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपिटल राशि रू. 50.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 20.33 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 07.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
Half yearly free health camp for villagers i.e. Kumhra Judwani, etc	0.50 lakh
Provision of two handpump at village Kumhra Judwani (at Village panchayat bhawan and School) for drinking water facility	3.00lakhs
Plant distribution at village i.e. Kumhra Judwani, @1000	0.50 lakhs
Maintenance of Village road (1000m length)	2.00lakhs

ITI Training for 5girls and 5 boys @10000.00 per student	1.00lakhs
Library facility at Kumhra School	0.50 lakhs

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 21740 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In barrier zone	Karanj, Achar, Khamer, Neem, white kastar, chirol, Sissoo, and other local species	3000
2	Non-mining zone + Road side within lease area	Karanj, Khamer, Neem, white kastar, chirol, Sissoo, and other local species	4460
3	backfilled area	Karanj, Khamer, Neem, white kastar, chirol, Sissoo, and other local species	12280
4	For village distribution	Mango, Guava, Achar Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये ।
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No 10068/2023 Ms. Uma Sharma M P INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, 101, FIRST FLOOR, ATULYA IT PARK, KHANDWA

ROAD, INDORE Distt.- INDORE (M.P.) 452001. .Prior Environment Clearance for M/s MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building "IT Park-III" at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is - 147058 m2. Cat. 8 (a) Building / Construction Project-B2.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Commercial Building "IT Park-III" [Total Plot Area-29105.0 sqm, Total Built-up Area-1,47,058 sqm] at (Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375) Village-Pipliyarao, Tehsil-Indore, District-Indore, (MP).

The case was presented by Shri Shbham Dubey Env. Consultant from M/s. Envisolve and PP Ms. Uma Sharma, Executive Engineer, M/s M.P. Industrial Development Corporation, District-Indore in the 664th meeting held on 28.07.2023. Wherein PP submitted that M/s MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building "IT Park-III" at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is 147058 m2. As per EIA notification S.O.1533 issued on 14th Sep 2006 and its subsequent amendments the proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m2 and < 150000 m2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

The Salient features of the project:-

- MPIDC (MP Industrial Development Corporation) is the Single Window Secretariat for Investment Promotion and Facilitation in the state since 2004.
- MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building ***"IT Park-III"*** at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 147058 m^2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m^2 and < 150000 m^2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

Project Title	Construction of commercial building *"IT PARK-III"* By MPIDC
Total Plot Area	29105 m^2
Total Built up Area	Total Built up Area-147058 m2

	FAR-104354 m2 Non FAR-42704 m2
Location of Project	Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh.
Geological Location	Latitude-22°41'2.64"N Longitude- 75°52'7.35"E
Building Configuration	Basement 1 + Basement 2 + Ground floor + 1st floor + 2nd floor + 3rd Floor + 4th floor + 5th floor + 6th floor + 7th floor + 8th floor + 9th floor +10th floor + 11th floor + 12th floor + 13th floor + 14th floor + 15th floor +16th floor + 17th floor + 18th floor + 19th floor
Estimated Project Cost	Total Cost-INR 386.98 Cr (Approx.)
Height of the Building	75 mtrs

S.No.	Particulars	Proposed Quantity/Area
1.	Permissible Ground coverage @ 30% Permissible Ground coverage @ 29%	8731.5 sq.mt. 8440.45 sq.mt.
2.	Permissible FAR @ 3.0 Permissible FAR @ 2.9	87315 sq.mt. 84404.5 sq.mt.
3.	No. of Floors	Basement 1 + Basement 2 + Ground floor + 1st floor + 2nd floor + 3rd Floor + 4th floor + 5th floor + 6th floor + 7th floor + 8th floor + 9th floor +10th floor + 11th floor + 12th floor + 13th floor + 14th floor + 15th floor +16th floor + 17th floor + 18th floor + 19th floor
4.	Activities in the complex	Offices, Data Centre, Hotel, Restaurant/Food Court
5.	Total No. of Restaurants seats	400 Nos
6.	Proposed Green cover area	2910.5 sq. mt. (10%)

7.	Parking	Basement Parking 1= 254 Basement Parking 2 = 233 Ground floor parking = 323

S.No.	Particulars	Proposed Quantity/Area
8.	Power Requirement	9000 KVA
9.	DG set details	6 No's DG set of 1500 KVA each
10.	Water Requirement	Total Water : 436.14 KLD Fresh Water : 234.29 KLD Flushing : 167.31 KLD Gardening : 14.55 KLD HVAC : 20 KLD
11	• STP • Rainwater Harvesting Quantity • Garbage Disposal • Service Block (Substation, DG Set, etc.)	• 450 KLD • 2 No of RWH Pits • Yes, as per norms • Yes, as per norms

After detail discussion and deliberation, committee asked PP to submit the following information/clarification for further consideration of the project:

1. Revised green area calculation with their location on lay-out map.
2. PP's commitments that :
    - Green area shall be increased upto 18.5 % of total project area and green cover area 25%.
    - Highest Griha rating i.e. "5" shall be obtaioned by the Proponent.
    - Street pole lightning shall based on solar power.
    - Provision for solar light up to 30% of the total requirement. All street light should be solar lighting.
    - Re-assessment of the EV charging stations.
3. Total vehicles load include existing and visitors numbers /floating population in terms of ECS.
4. Re-assess water requirement quantity/water balance chart etc..
5. Schematic diagram of STP with provision of treated sewage BOD as 3.0 mg/lit and incorporation of ultra filteratation unit.
6. Re-assessment of Rain Water Harvesting pits.
7. Revised plantation scheme and species as suggested by the committee during presentation.

8. Revised CER the activities shall includes distribution of school uniform in the Rajpura , Choral range Bai villages, distribution of mediacl equipments in the nearby PHC's , Veternary hospitals, distribution of Aganwadies etc.

The project proponent submitted clarification on 26.08.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 664th meeting held on 28.07.2023.

The point wise query reply is as given below:

S.No	ADS	Reply
1.	Revised green area calculation with their location on lay-out map.	Revised green area planning has been increased to 18.58% from 10%. A detailed Green belt plan has been submitted.
2.	Commitments from PP to be submitted for the following- • Green area shall be increased upto 15 % of total project area. • Highest Griha rating i.e., "5" shall be obtained by the Proponent. • Solar power contribution shall be 30% of total power consumption. • Street pole lightning shall based on solar power. • Re-assessment of the EV charging stations.	Undertaking for the compliance of the points has been submitted.
3	Total vehicles load includes existing and visitors' numbers /floating population in terms of ECS	Total 949 ECS is proposed as parking & multilevel parking if required shall also be planned.
4	Re-assess water requirement quantity/water balance chart etc.	The water requirement quantity and water balance chart has been furnished.
5	Schematic diagram of STP with provision of treated sewage BOD as 3.0 mg/lit and incorporation of ultra filtration unit.	Flow chart of STP is attached, UF unit already included. (Typical flow chart of STP is attached it may be change as per vendor's design)
6	Re-assessment of Rain Water Harvesting pits	RWH Calculation is attached as annexed.

7	Revised plantation scheme and species as suggested by the committee during presentation.	Revised Plantation scheme is attached as annexed.
8	Revised CER details.	As annexed.

- MPIDC (MP Industrial Development Corporation) is the Single Window Secretariat for Investment Promotion and Facilitation in the state since 2004.
- MPIDC Ltd is proposing the construction of a commercial building "IT Park-III" at Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 147058 m2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m2 and < 150000 m2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

The total CO2 (t/annum) emission because of the project during construction has been summarized below:

Emission Scenario	**CO2 (t/Annum)**
Scope 1	53856.66
Scope 2	5067.117
Scope 3	6668.54232
Total CO2	65592.319

After deliberations the PP was directed to submit following information along with the supporting documents:

- The lay-out map was not clear hence, PP was asked to submit revised coloured lay-out map clearly depicting the green areas in the project.
- At least 30 % of total power consumption shall be met through solar power installations, undertaking in this regard with proposal to be submitted.
- Total number of EV charging stations and their details to be submitted.
- Details of STP with designed parameters to be re-submitted.

- Revised CER the activities shall includes distribution of school uniform in the Rajpura , Choral range Bai villages, distribution of mediacl equipments in the nearby PHC's , Veternary hospitals, distribution of Aganwadies etc.

The project proponent submitted clarification on 04.11.2023 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 688^{h} meeting held on 12.10.2023.

Hence this case was scheduled in agenda in the SEAC 697th meeting dated 23.11.2023 w.r.t. query reply. The PP submitted the reply of query as above and the CER details as follows :-

S.No.	Particulars	Total (Lacs)	First year (Lacs)	Second Year (Lacs)	Third Year (Lacs)
1	Distribution of School uniforms in Rajpura Village and Choral Bai range villages: Baigram, Gavhalu and Dhawadiya	10	5	5	-
2	Distribution of medical equipment's in the nearby PHC's	75	–	–	75
3	Distribution of medical equipment's in the nearby veterinary hospital	50	–	50	–
4	Distribution of medical equipment's in the nearby Anganwadies	25	25	–	–
5	Solar Street Light Arrangement in Village Rangwasa	20	–	20	–
6	Plantation arrangement in village Rangwasa	80	–	50	30
7	**We will develop Eco Park at Talab adjacent to Vill. Karondiya.** **Following work has been proposed**	200 Rs. 200 (This activitiy shall be started after 3 year)	-	-	-
	• Development of Eco track around the talab.				
	• All the street light, garden lights will be solar based.				
	• Development of nature trails				

	• Greening and Mido development and deepening of pond.				
8	Sill Develipment Program in Rajpura Village and Choral Bai range villages: Baigram, Gavhalu and Dhawadiya with the help of IIT, Indore or other govt. agencies	20	–	10	10
9	Development of habitat in Ralamandal	20	5	10	5
10	Development of City Forest in Deoguradiya with the consultation of Forest Department.	80	–	80	–
	Total	**580**	**35**	**225**	**120**

समिति द्वारा विस्तृत परीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रावधानों में निम्नानुसार विसंगति पाई गई हैः–

- वन भूमि पर किसी भी अन्य ऐजेन्सी द्वारा कार्य प्रतिबंधित है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सीईआर के अंतर्गत प्रावधानित राशि संबंधित विभाग को देय होगी।
- देव गुराडिया पहाडी शहर की सीमा में ही स्थित है। अतः उसमें भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप सिटी फोरेस्ट के रूप में विकसित किया जायें तथा उक्त कार्य वन विभाग द्वारा ही किया जायें। समिति द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया था।
- ईको पार्क विकास हेतु रूपये 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है, किन्तु उक्त कार्य किस वर्ष में किया जावेगा, स्पष्ट नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

The project proponent submitted clarification above query on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the SEAC 697th meeting dated 23.11.2023.

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for "Construction of Commercial Building "IT PARK-III" By MPIDC"Khasra No. P144, P154, P155, P365 & 375 near Crystal IT Park, Vill. Pipliyarao, Ring Road, Indore, M.P.** Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

I. Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low-lying area.The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. 06 Diesel power generating sets 1500 kVA*6 nos.proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

xi. The gaseous emission from DG sets 1500 kVA*6 nos., shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
iii. The total water requirement during operation phase is 315 KLD out of which 188 KLD is fresh water requirement and 188KLD will be the total recycled water generated, out of which 128 KLD recycled water will be used for flushing, 15 KLD will used for Road and car washing.
iv. The BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and

recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built-up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiv. For rainwater harvesting, 07 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 28.26m^3/hr.

xv. Mesh will be provided at the roofso that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xvi. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWA.

xvii. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xviii. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xix. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xx. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

xxi. Sewage shall be treated in the MBBR followed by ultrafiltration based STP (Capacity - **250** KLD).The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xxii. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 250 KLD capacity (based on MBBR followed by Ultrafiltration) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxiii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxiv. Basic facilities like wash rooms and toilets (02 nos.) for the use by employees, guard, gardeners, outside drivers and house hold workers shall be provided to avoid open defecation in the nearby areas.

xxv. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxvi. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Looking to the use of e-vehicles atleast three battery charging points per towers in the projects shall be provided.

ii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

iii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iv. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such asbuilding orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

v. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

vi. **Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 30% of the demand load or as per the state level /local building bye-law's requirement, which ever is higher.**

vii. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. Estimated solid waste 2560.95 Kg/day consisting Organic waste 1536.57 Kg/day and non- organic waste 768.28 Kg/day, Inert waste 256.09 Kg/day shall be treated and disposed off as per the provision made in the MSW Rules 2016 and Plastic Waste Rules .
ii. The expected E- waste 1355.54 Kg/Annum shall be disposed off in accordance to the E & E-waste Rules,
iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
vi. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

i. **Total 727 trees shall be planted in the area of 5410 m^2 (18 % of total plot area) within the project site with following time frame and species and nos.**

- Year Wise Plantation Details :
- 1st Year – 250 nos.
- 2nd Year – 250 nos.
- 3rd Year-227 nos.

Sr. No.	Trees Common Name	Scientific Name	No of Trees
1	Azadirachta Indica	Neem	100
2	Mimusops Elengi	Molshree	80
3	Delonix regia	Gulmohar	50
4	Cassia fistula	Amaltas	45
5	Mangifera indica	Aam	50
6	Putranjiva roxburghii	Putranjiva	42
7	Saraca asoca	Ashoka	50
8	-	Sita Ashoka	40
9	Neolamarckia cadamba	Kadam	30
10	Magnolia champaca	Gobar Champa	100
11	Pongamia pinnata	Karanj	50
12	Ficus religiosa	Peepal	40
13	Dalbergia sissoo	Shisham	50
	Total		**727**

ii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points
   d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Total proposed Parking's arrangement for 949ECS (Basement 1&2 parking 446 ECS, stilt parking-237 ECS and 266 ECS for open parking).

v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time

and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & Corporate Environment Responsibility

i. For Environment Management PlanPP has proposed Rs.4630.0 Lacs as capital and Rs. 132.0 Lacs as recurring cost for this project.
ii. For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs 580.0 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).

S.No.	Particulars	Total (Lacs)	First year (Lacs)	Second Year (Lacs)	Third Year (Lacs)
1	Distribution of School uniforms in Rajpura Village and Choral Bai range villages: Baigram, Gavhalu and Dhawadiya	10	5	5	-
2	Distribution of medical equipment's in the nearby PHC’s and nearby Anganwadies	100	33	33	33
3	Distribution of medical equipment's in the nearby veterinary hospital	50	17	17	17

4	Solar Street Light Arrangement in Village Rangwasa	20	–	20	–
5	Plantation arrangement in village Rangwasa	80	50	30	–
6	We will develop Eco Park at Talab adjacent to Vill. Karondiya. Following work has been proposed	200	67	67	66
	1.Development of Eco track around the talab.				
	2.All the street light, garden lights will be solar based.				
	3.Development of nature trails				
	4.Greening and Mido development and deepening of pond.				
7	Skill Development Program in Rajpura Village and Choral Bai range villages: Baigram, Gavhalu and Dhawadiya with the help of IIT, Indore or other govt. agencies	20	–	10	10
8	Development of habitat in Ralamandal	20	5	10	5
9	Development of City Forest in Deoguradiya with the consultation of Forest Department.	80	32	28	20
	Total	580	209	220	151

iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly reports.

v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC).
iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

<u>अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु –</u>

प्रकरण क्रमांक **8007/2020** M/s. Satguru Cement (P) Ltd., को आगामी बैठक दिनांक 16/12/2023 में समीक्षा हेतु अतिरिक्त एजेण्डा में रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

700वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 दिसम्बर 2023

अध्यक्ष महोदय की अनुमाति से शुद्धि पत्र।

Case No 10706/2023 Shri Ranjeet Dayma S/o Shri Bherulal Dayma, Lessee, R/o House No. 12, Ward No. 05, Uparli Toli, Tehsil-Alot, District-Ratlam (MP)-457114, Prior Environment Clearance for Maukhedi Crusher Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (Stone-5130, Gitti-3100, M-Sand-2030 cum per year) (Khasra No. 501/1), Village Maukhedi, Tehsil Alote, District Ratlam (M.P.) -TOR.

एसईएसी की 699वीं बैठक दिनांक 08/12/2023 को टॉर हेतु कार्यवाही विवरण में निम्न अनुशंसा को पढ़ा जावे, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी :–

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।